दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

फरवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- प्रदेश सरकार क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये सिडबी से लेगी 523 करोड़ रुपए ऋण 3
- सुल्तानपुर झील पर आयोजित किया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे 3
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने रखी 'री-सर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम' की आधारशिला 4
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए 124 प्रजातियों के लगभग 28,000 प्रवासी पक्षी 4
- कैबिनेट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंजूरी 5
- शहरी स्थानीय निकायों का बजट 6
- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,पंचकूला 6
- जल सुरक्षा सुनिश्चितिकरण बांध परियोजना 7
- जेलों में होने वाले सुधार की होगी रैंकिंग 7
- नूंह स्थित लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन 7
- दीपा मलिक को मिला एशियाई ऑर्डर पुरस्कार, 2022 8
- कला रामचंद्रन बनीं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर 8
- श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला मुंडलाना के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ 8
- हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ ग्रुप-सी काडर के लिये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 9
- आशा वर्कर्स को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहा हरियाणा 10
- हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द 10
- गूगल ऑफिस की तर्ज़ पर लघु सचिवालय में विशेष कक्ष 11
- किसान ड्रोन का उद्घाटन 11
- एचएसबीटीई ने 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के साथ किया समझौता 12
- एक अनूठे कार्यक्रम 'पदमा'की हुई शुरुआत 13
- राखीगढ़ी 13
- प्रदेश के 100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले 31 नागरिक अस्पतालों में मुहैया होगी केटरिंग सेवा 14
- मुख्यमंत्री ने हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी की वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किये 14
- प्रदेश के हर गाँव व शहर में लगाए जाएंगे 'माइक्रो एटीएम' 15
- मुख्यमंत्री ने किया एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ 15
- 38वीं राज्यस्तरीय पशुधन प्रदर्शनी 16

नोट :

हरियाणा

प्रदेश सरकार क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये सिडबी से लेगी 523 करोड़ रुपए ऋण

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- यह ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिये लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पदमा स्कीम व प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिये किया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई-नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को ज्यादा-से-ज्यादा नौकरियाँ भी मिलेंगी।
- इसके तहत प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पदमा स्कीम की रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा।
- इसके तहत वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट का लक्ष्य लेकर हर ब्लॉक में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इससे उस क्षेत्र के संबंधित उद्योगों को सीधे फायदा मिलेगा।

सुल्तानपुर झील पर आयोजित किया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे

चर्चा में क्यों ?

- 2 फरवरी, 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में वर्ल्ड वेटलैंट डे (विश्व आर्द्रभूमि दिवस) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के 'बखिरा वन्यजीव अभयारण्य' और गुजरात के 'खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य' को रामसर स्थल घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- इन दोनों अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है।
- ज्ञातव्य है कि मई 2021 में गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और झज्जर के भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि) के रूप में घोषित किया गया था।
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम-झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गाँव में 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल, 1971 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। 5 जुलाई, 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- आर्द्रभूमि दिवस समारोह के अवसर पर आर्द्रभूमि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित वेबिनार की एक शृंखला आयोजित की जा रही है। हरियाणा में पक्षियों की संख्या पर एक अभ्यास भी पूरे राज्य के विभिन्न भागों में चल रहा है।
- इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि (भौतिक रूप से) पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (एसएसी) द्वारा तैयार किया गया 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस' भी जारी किया गया, जो पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और कुशलता से उपयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किये गए थे।
- आर्द्रभूमि पर संधि को लागू करने की तिथि के प्रतीक के रूप में हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह लोगों और धरती के लिये आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय 'लोगों और प्रकृति के लिये आर्द्रभूमि की भूमिका' है, जो मानव और धरती के स्वास्थ्य के लिये आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये किये जाने वाले कार्यों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
- उल्लेखनीय है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिक रूप से विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो 40 प्रतिशत जैव विविधता को आश्रय देते हैं। ये पानी को अवशोषित करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं और जल स्तर को रिचार्ज करते हैं। ये वैश्विक कार्बन का लगभग 1/3 भाग संग्रहीत करते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, अगर इन्हे संरक्षित नहीं किया जाता है, तो वे कार्बन उत्सर्जन का स्रोत भी हो सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने रखी 'री-सर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम' की आधारशिला

चर्चा में क्यों ?

- 3 फरवरी, 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के 53वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने री-सर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की आधारशिला रखी। इस तकनीक के माध्यम से देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन हासिल किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) एक ऐसी तकनीक है, जो पानी के पुन: संचार और पुन:उपयोग पर निर्भर करती है। इससे किसान कम जोत में भी अधिक मछली उत्पादन कर सकते हैं।
- इस प्रणाली में आयताकार या वृत्ताकार टैंक में कम जगह में अधिक मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें मछली पालन में दूषित हुए पानी को बॉयो फिल्टर टैंक में डाला जाता है, फिर इसे फिल्टर करके वापस मछली वाले टैंक में भेज दिया जाता है।
- इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने रोजगारोन्मुखी योजनाओं का और अधिक क्रियान्वयन करने व प्राकृतिक खेती को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये किसानों की आय में वृद्धि पर बल दिया।
- विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय में दो दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान, सहायक विज्ञान, गृह विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी, कृषि व्यवसाय, मत्स्य विज्ञान, प्रतियोगी एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है।
- इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता की पुस्तकों का चयन किया जाना है, ताकि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय में उनकी उपलब्धता आसानी से हो सके।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए 124 प्रजातियों के लगभग 28,000 प्रवासी पक्षी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (वन्यजीव) निरीक्षक राजेश चहल ने बताया कि इस शीत ऋतु में गुरुग्राम के सुल्तानपुर गाँव में स्थित राष्ट्रीय उद्यान (सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य) को 28,026 प्रवासी पक्षियों ने घोंसला बनाने के लिये चुना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि 124 पक्षी प्रजातियाँ पहले ही यहाँ आ चुकी हैं, जबकि ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, रेड हेडेड फाल्कन, इंपीरियल ईगल, कॉमन केस्ट्रेल, व्हाइट टेल्ड लैपविंग, ब्लैक टेल्ड गॉडविट को कई वर्षों के बाद यहाँ देखा गया है।
- हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम.एल. राजवंशी ने बताया कि भारत विभिन्न पक्षी प्रजातियों के प्रजनन और विशेष मौसम में पालने के लिये सबसे अनुकूल परिदृश्यों में से एक है। हरियाणा का तापमान इसे साइबेरिया और दुनिया के अन्य हिस्सों की कठोर जलवायु से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिये उपयुक्त परिदृश्य बनाता है।
- राजेश चहल ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर के बीच लगभग 29 देशों से सर्दियों में प्रवास के लिये पक्षी आते हैं और मार्च तक वापसी की यात्रा करते हैं। इस साल सर्दी शुरू होने से काफी पहले ही राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया था, चूँकि पार्क में पक्षियों के लिये एक आदर्श आवास है, इसलिये हर साल बड़ी संख्या में पक्षी आराम करने और भोजन करने के लिये हज़ारों मील की दूरी पर इस आर्द्रभूमि में आते हैं।
- हर साल पक्षियों की संख्या और क्षेत्र में आने वाली प्रजातियों को नोट करने के लिये पार्क में पक्षियों की गिनती की जाती है। इससे प्रवास के पैटर्न और पार्क की पारिस्थितिकी को समझने में मदद मिलती है।
- हाल ही में 30 जनवरी को संपन्न हुई पक्षी गणना के दौरान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार प्रवासी पक्षी, जैसे- ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, रेड हेडेड फाल्कन, इंपीरियल ईगल, कॉमन केस्ट्रेल, व्हाइट टेल्ड लैपविंग, ब्लैक टेल्ड गॉडविट को पहली बार देखा गया।
- सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पक्षियों, उभयचरों और तितलियों सहित जीवों की 600 से अधिक प्रजातियाँ हैं। पक्षियों की 417 से अधिक प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, 16 स्तनपायी प्रजातियाँ, तितलियों की 40 प्रजातियाँ, 16 सरीसृप और 5 उभयचर प्रजातियाँ हैं।
- राजेश चहल ने बताया कि आमतौर पर पार्क में उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वेडर (पानी पर निर्भर पक्षी), बत्तख (थोड़ा गहरे पानी पर निर्भर) और वार्बलर (रीड पसंद करते हैं)।
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2020 के अनुसार, भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की 1,220 प्रजातियों में से 280 लंबी दूरी की प्रवासी हैं, जबकि 116 उपमहाद्वीप की प्रवासी हैं और शेष प्रजातियाँ आमतौर पर देश की सीमाओं के भीतर रहती हैं।

कैबिनेट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 8 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना'(एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) से प्राप्त सत्यापित आँकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 रुपए वितरित किये गए।
- योजना के तहत सीआरआईडी उन परिवारों का सत्यापित डेटा प्रदान करेगी जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए वार्षिक से कम या उसके बराबर है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहचान संख्या है। पात्र लाभार्थियों की पहचान सीआरआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से की जाएगी।
- एमएमपीएसवाई योजना के तहत, 6000 रुपए प्रति परिवार की राशि के लिये पात्र लाभार्थी पाँच केंद्रीय योजनाओं अर्थात् पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई का लाभ पाने के हकदार होंगे।
- 6000 रुपए की बीमा राशि का उपयोग लाभार्थी की पात्रता के अनुसार उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिये किया जाएगा।

नोट :

- केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में से किसी भी योजना में शामिल होने के समय लाभार्थी अंशदान की पहली किश्त का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- योजना को जारी रखने के कारण देय आगामी प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में या बीमा कंपनी को किया जाएगा। तीन मानधन योजनाओं (पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई) के पात्र लाभार्थियों के लंबित बकाया/प्रीमियम का भुगतान भी पहली अप्रैल, 2020 से एमएमपीएसवाई के तहत किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकायों का बजट

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने बताया कि इस वर्ष शहरी स्थानीय निकायों का बजट 7 प्रतिशत रखने के साथ कम आय वाले स्थानीय निकायों के लिये 2 प्रतिशत बजट अलग से रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को स्थानीय स्तर पर 15 मार्च से 31 मार्च तक अपना बजट तैयार कर मुख्यालय को भेजना होगा।
- इन निकायों को आय बढ़ाने और निकायों द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिये नए वित्तीय स्रोत बनाने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर के लिये नई विज्ञापन नीति बनाई जाएगी।
- प्रदेश के सभी शहरों में समग्र विकास की ओर ध्यान देने के लिये अमृत-2 योजना में सभी शहर शामिल होंगे, जबकि इससे पहले अमृत-1 योजना में 18 शहरों को शामिल किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नगरीय निकायों का प्रशासन हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार किया जाता है, जिसमें वर्ष 2020 में दूसरा संशोधन किया गया है।
- भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं।
- इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,पंचकूला

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 31 दिसंबर, 2021 को आयोजित बैठक से संबंधित मिनट्स ऑफ मीटिंग का प्रकाशन किया गया, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा चौकियों एवं आयुर्वेद संस्थान सहित कई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से 8.04 हेक्टेयर क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
- औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये आयुष मंत्रालय द्वारा पंचकूला में स्थापित किया जा रहा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान न केवल औषधीय पौधों के संरक्षण में, बल्कि जनता को प्रकृति की सुरक्षा से जोड़ने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- आयुर्वेद एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरि इसके प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इसे अथर्ववेद का एक उपवेद माना जाता है।

नोट :

जल सुरक्षा सुनिश्चितिकरण बांध परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- 13 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने नूंह ज़िले के पथखोरी में जल सुरक्षा सुनिश्चितिकरण बांध परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य राज्य में अरावली और शिवालिक पहाड़ियों में झरनों के माध्यम से बहने वाले पानी को बांध बनाकर संरक्षित करना है, ताकि वर्षा जल का उपयोग वर्षा के बाद भी पूरे वर्ष पेयजल और सिंचाई के प्रयोजनों के लिये किया जा सके।
- इस परियोजना से नूंह ज़िले के 9 गाँवों की पेयजल और सिंचाई की ज़रूरतें पूरी होंगी, जिसके अंतर्गत बांध के बनने से 224 हेक्टेयर मीटर पानी का संग्रहण हो सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास संबंधी कई जानकारियाँ दीं।
  - दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिये 263 करोड़ रुपए से रेनी वेल योजना की शुरुआत की गई है।
  - 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें केएमपी एक्सप्रेस-वे सहित यमुना नदी से पानी लिया जाएगा।
  - मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल बोने के लिये 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है।

जेलों में होने वाले सुधार की होगी रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

- 14 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ज़िला सचिवालय सभागार में जेल विभाग के सुधार के मद्देनज़र आयोजित सेमिनार में हरियाणा की 20 जेलों की रैंकिंग जारी करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में स्थित कुल 20 जेलों की रैंकिंग निर्धारित की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ जेल के रूप में पहचान कायम करने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली जेल के अधीक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस विभाग के उप-पुलिस अधीक्षक स्तर की फोन की सुविधा के अनुरूप जेल अधीक्षकों को भी फोन की सुविधा देने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल विभाग के सुधार में जेल स्टाफ की अहम भूमिका है, जेल अधीक्षक आपराधिक प्रवृत्ति वालों के आचरण में बदलाव लाने में सक्रियता दिखाएँ।
- उन्होंने जेल अधीक्षकों को प्रेरित किया कि वे सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने में अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। जेलों का क्लासीफिकेशन करें कि कैसे और सुधार हो।

नूंह स्थित लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 14 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह स्थित लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कंट्रोल रूम से ज़िले में आपराधिक गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि दृश्यम कंट्रोल रूम की मदद से पुलिस प्रशासन को काफी सहूलियत होगी। अब तीसरी आँख की ज़द में ज़िले की हर घटना रिकॉर्ड होगी।
- ज़िले में आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये ज़िले के मुख्य चौक-चौराहों व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में करीब 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की खास बात है कि 7 किमी. तक दिन-रात ये कैमरे हर हरकत को कैद कर सकते हैं व 100 मीटर तक किसी भी चीज़ को ज़ूम कर उसका सही आंकलन किया जा सकता है।
- नूंह ज़िले के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि अभी तक 35 लाख रुपए की लागत इस हाईटेक दृश्यम केंद्र पर आई है। इस केंद्र में आठ एलईडी लगाई गई हैं। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के साथ-साथ वे स्वयं भी अपने मोबाइल द्वारा नज़र रख सकते हैं।

दीपा मलिक को मिला एशियाई ऑर्डर पुरस्कार, 2022

चर्चा में क्यों ?

- 14 फरवरी, 2022 को हरियाणा की दीपा मलिक को एशियाई ऑर्डर पुरस्कार, 2022 से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- टोक्यो पैरालंपिक, 2022 अब तक के सभी पैरालंपिक में भारत के लिये सर्वाधिक सफल पैरालंपिक रहा है, जिसमें भारत को कुल 19 मेडल प्राप्त हुए। इस सफलता में दीपा मलिक का भारतीय पैरालंपिक समिति की प्रमुख के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- उल्लेखनीय है कि दीपा मलिक हरियाणा के भैंसवाल (सोनीपत) से संबंधित एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रियो पैरालंपिक, 2016 में 4.61 मीटर तक गोला फेंक कर शॉट-पुट में रजत पदक जीता था। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला हैं।
- पैरालंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया है।

कला रामचंद्रन बनीं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर

चर्चा में क्यों ?

- 15 फरवरी, 2022 को आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनीं हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि कला रामचंद्रन 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं।
- कला रामचंद्रन ने अपनी प्राथमिकताएँ गिनाते हुए बताया कि गुरुग्राम में ट्रैफिक को सूचारु रूप से चलाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष ज़ोर रहेगा। महिला और साइबर अपराध पर रोक लगाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
- उल्लेखनीय है कला रामचंद्रन अभी तक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव के तौर पर पदभार संभाल रही थीं।
- ज्ञातव्य है कि गुरुग्राम में पुलिस कमिशरी 2007 में बनी थी। इससे पहले गुरुग्राम में एसपी नियुक्त होते थे। कमिश्नरी बनने के बाद सबसे पहले महेंद्रलाल गुरुग्राम के पहले पुलिस कमिश्नर बने थे। इस दौरान आठ पुलिस कमिश्नर बने जो सभी पुरुष थे।

श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला मुंडलाना के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण के साथ श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला मुंडलाना के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये गौशालाओं में लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे गौशाला की खुद की आमदनी हो सके। साथ ही मुंडलाना गौशाला को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देते हुए घोषणा की कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार आर्थिक मदद देगी।
- उप-मुख्यमंत्री ने मुंडलाना स्थित श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला में नव-निर्मित मंदिर का भी लोकार्पण किया।
- उप-मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हिसार तथा पिंजौर की गौशालाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अब गौशालाओं को स्वयं की आय अर्जन की ओर आगे बढ़ाना होगा। हिसार के लाडवा की गौशाला साबुन व सर्फ बनाती है और गौमूत्र की पैकिंग भी कर बिक्री करती है। पिंजौर गौशाला में गौमूत्र व गोबर से पेंट बनाया जाता है।
- नया गाँव में बायोगैस प्लांट की स्थापना का सफल प्रयोग रहा है, जिससे निर्मित गैस से पूरे गाँव को आपूर्ति की जाती है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंडलाना गौशाला में भी बायोगैस प्लांट लगवाएँ। इस दिशा में यह गाँव एक आदर्श गाँव के रूप में स्थापित हो। इसके लिये एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि हिसार व पिंजौर आदि गौशालाओं का अध्ययन कर लघु उद्योग की ओर कदम बढ़ाए।

हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ ग्रुप-सी काडर के लिये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ (डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और (जूनियर लेक्चर असिस्टेंट) ग्रुप-सी काडर के लिये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह नीति राजकीय कॉलेजों में नियमित आधार पर कार्यरत कॉलेज काडर ग्रुप- सी/मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, जहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 80 या उससे अधिक हो, पर लागू होगी।
- उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुसार डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और ध्जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की विभिन्न स्थानों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से तैनाती सुनिश्चित करने तथा उनमें कार्य संतुष्टि बढ़ाने व उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से इस नीति को तैयार किया गया है।
- इस नीति के अंतर्गत सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे। हालाँकि, पदोन्नति, सीधी भर्ती और लोक हित में आवश्यकतानुसार पदों की भर्ती करने हेतु स्थानांतरण/नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के बाद या विभाग की अनिवार्यता के अनुसार क्रियान्वित किए जाएंगे।
- इस नीति के तहत पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को किसी भी सरकारी कॉलेज या राज्य में कहीं भी या लोक हित में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इस नीति के तहत स्थानांतरण/ नियुक्ति के लिये आयु और कम्पोजिट स्कोर को भी ध्यान में रखा जाएगा। रिक्ति के लिये आवंटन का निर्णय निर्धारित 80 अंकों में से कर्मचारी द्वारा अर्जित कुल संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम अंक अर्जित करने वाला कर्मचारी किसी विशेष रिक्ति के खिलाफ स्थानांतरण का हकदार होगा।
- किसी रिक्ति के समक्ष कर्मचारी के दावे को तय करने के लिये आयु प्रमुख कारक होगी, क्योंकि इसमें कुल 80 अंकों में से 60 अंकों की वरीयता होगी। हालाँकि, विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा अधिकतम 20 अंकों के विशेष लाभ का दावा किया जा सकता है।
- यदि पति और पत्नी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम में कार्यरत हैं, तो उस स्थिति में दोनों में से केवल एक ही पाँच अंकों के लाभ का दावा कर सकता है और उसके लिये उसे स्वयं घोषणापत्र (डेक्लारेशन) जमा करवाना होगा कि उसके पति या पत्नी ने इस श्रेणी (कपल केस) का लाभ नहीं लिया है। यह स्वयं घोषणापत्र ड्राइव में भाग लेते समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नोट :

आशा वर्कर्स को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहा हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार आशा कार्यकर्त्ताओं की जायज मांगों को लेकर बहुत संजीदा है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता के अनुसार हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर पारिश्रमिक प्रदान कर रही है, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार अन्य राज्यों की तुलना में आशा वर्कर्स को सर्वोत्तम पारिश्रमिक देने में भी शीर्ष पर है।
- संपूर्ण देश में हरियाणा की आशा कार्यकर्त्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक मानदेय राज्य बजट से दिया जा रहा है।
- वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 20,001 आशा कार्यकर्त्ता, आशा पे-ऐप (ASHA PayApp) पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें भारत सरकार के नियमानुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'विभिन्न गतिविधियाँ करने के उपरांत केवल परफॉरमेंस बेस्ड इंसेंटिव'दिये जाने का प्रावधान है।
- परंतु हरियाणा सरकार ने राज्य बजट से आशा कार्यकर्त्ताओं के लिये अतिरिक्त मानदेय हेतु 154.45 करोड़ रुपए का प्रावधान निम्नलिखित रूप में किया हुआ है-
  - 4000 रुपए मासिक निश्चित मानदेय
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य-आधारित अर्जित मासिक राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय।
  - कार्य-आधारित 7 प्रमुख गतिविधियों के लिये 750 रुपए अतिरिक्त मानदेय।
  - आशा की मृत्यु उपरांत परिवार की आर्थिक सहायता के लिये तीन लाख रुपए।
- मार्च से नवंबर, 2021 तक 5033 (25.16 प्रतिशत) आशा कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक मानदेय दिया गया है, जिसमें से 38 आशा कर्मियों को प्रति माह 18,000 रुपए से अधिक, 318 आशा कर्मियों को 18,000 रुपए से 14,000 रुपए तक तथा 4677 आशा कर्मियों को 14,000 रुपए से 10,000 रुपए तक प्रति माह दिया गया है।
- इसी प्रकार, शेष 14968 आशा कर्मियों को 10000 रुपए से 6000 रुपए प्रति माह तक दिया गया है, जिनमें से 6000 रुपए प्रति माह लेने वाली आशा कर्मियों की संख्या पूरे राज्य में केवल 20 है।
- वहीं देश में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (हरियाणा) द्वारा आशा वर्कर को एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट फोन सीयूजी सिम 30 जीबी डाटा एवं असीमित टॉक-टाइम के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश है।
- उल्लेखनीय है कि आशा कार्यकर्त्ताएँ समाज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं, परंतु राज्य में उनके स्वास्थ्य-कल्याणार्थ कोई योजना नहीं थी, इसीलिये हरियाणा सरकार ने उन्हें AB-PMJAY का लाभ देने निर्णय किया, इसके तहत आशा और उसके परिवार के सदस्यों को हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में पाँच लाख रुपए प्रति वर्ष तक का इलाज करवाने कि सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि एक महीने के अंदर इस मामले में निर्णय लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए और इस दौरान रोज़गार दाताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए।

नोट :

- विदित है कि 15 जनवरी, 2021 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 राज्य में लागू किया था। यह कानून नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो 'हरियाणा राज्य के निवासी' हैं।
- इसके बाद 3 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि उनके यहाँ कर्मचारियों का चयन योग्यता के अनुसार किया जाता है। हाईकोर्ट से कहा गया कि अगर कंपनियाँ अपने मनपसंद कर्मचारी नहीं चुन पाएंगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा।
- हाईकोर्ट में याचिकाकर्त्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अगर सरकार का यह फैसला लागू होता है तो रोज़गार को लेकर अराजकता फैल जाएगी और योग्य लोग वंचित रह जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।
- इस कानून के तहत निजी कंपनियाँ, सोसाइटियाँ, ट्रस्ट और साझेदारी फर्म भी शामिल हैं और यह उन नौकरियों पर भी लागू होता है, जो अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपए तक की मज़दूरी प्रदान करती हैं। केंद्र या राज्य सरकारें या इन सरकारों के स्वामित्व वाला कोई भी संगठन अधिनियम के दायरे से बाहर है।

गूगल ऑफिस की तर्ज़ पर लघु सचिवालय में विशेष कक्ष

चर्चा में क्यों ?

- 18 फरवरी, 2022 को हिसार की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय परिसर में गूगल ऑफिस की तर्ज़ पर बने मातृत्व कक्ष का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया बड़ी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के नवजात बच्चों के लिये एक अलग स्थान होता है। गूगल जैसी कंपनियों में महिला कर्मचारी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकती हैं। कुछ इसी तर्ज़ पर यह मातृत्व कक्ष बनाया गया है।
- सचिवालय परिसर में ऐसी माताएँ, जो अपने नवजात बच्चों के साथ आती हैं, एकांत न मिलने के कारण अपने बच्चों को ब्रेस्टफीडिंग नहीं करा पातीं। इस कारण से बच्चे भूख से रोने लगते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेस्टफीडिंग में महिलाएँ असहज महसूस करती हैं, ऐसे स्थलों पर महिलाएँ बच्चों के डायपर भी नहीं बदल पातीं।
- उपरोक्त समस्याओं को महसूस करते हुए उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर मातृत्व कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिये।
- मातृत्व कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य ऐसी माताओं को एकांत स्थान उपलब्ध करवाना है, जहाँ वे अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग करा सकें। कार्यों में लगने वाले समय के दौरान वे यहाँ आराम से बैठ भी सकेंगी।

किसान ड्रोन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 19 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर और चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की ड्रोन निर्माण सुविधाओं का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस एक ड्रोन-एज-ए-सर्विस (डीएएएस) कंपनी है।
- प्रधानमंत्री ने दो स्थानों पर ड्रोन निर्माण सुविधाओं का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया, जिसके परिणामस्वरूप 100 गाँवों में एक साथ 100 किसान ड्रोन उतारे गए।

नोट :

- इन 100 ड्रोनों ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिये 16 अलग-अलग राज्यों में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत कृषि छिड़काव अभियान शुरू किया।
- ज्ञातव्य है इस वर्ष की बजट घोषणाओं में प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में किसान ड्रोन के उपयोग का उल्लेख किया गया है।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने गुरुग्राम में डेफसिस सॉल्यूशंस से ड्रोन बनाने के लिये लीज पर जगह ली है। डेफसिस सॉल्यूशन की सुविधा उन्नत डिज़ाइन और प्रोटोटाइप परीक्षण क्षमताओं से लैस है।
- यह 2.5 एकड़ का संयंत्र ड्रोन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, टाइप सर्टिफिकेशन और प्रतिदिन 40 ड्रोन निर्माण क्षमता का केंद्र है।
- गरुड़ का प्रस्तावित चेन्नई संयंत्र 20 एकड़ की सुविधा पर स्थित है, जहाँ प्रतिदिन 100 ड्रोन उत्पादन की क्षमता और अगले दो वर्षों में 100,000 किसान ड्रोन के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। यह साइट प्रस्तावित आरपीटीओ (रिमोट पायलट ट्रेनिंग) सुविधा भी है, जिसका उद्देश्य इच्छुक ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करना है।
- गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा, 'प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गईं हमारी ड्रोन सुविधाएँ गरुड़ के भारत के पहले ड्रोन यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। यह स्टार्टअप छह लाख ड्रोन बनाएगा और 2025 तक प्रत्येक भारतीय गाँव में एक ड्रोन को तैनात करेगा।'

एचएसबीटीई ने 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के साथ किया समझौता

चर्चा में क्यों ?

- 21 फरवरी, 2022 को हरियाणा के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को स्टेनलेस स्टील प्रौद्योगिकी एवं एप्लीकेशन में सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीआई) ने 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के साथ एक समझौता किया।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन पर बोर्ड के सचिव राजेश गोयल और 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के विनिर्माण विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बिंदलिश ने हस्ताक्षर किये।
- बोर्ड के सचिव डॉ. राजेश गोयल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह एमओयू एक मील का पत्थर साबित होगा। 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के निदेशक विजय शर्मा ने कहा कि इस समझौते से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक नई श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त होगा और इस स्टेनलेस स्टील में पारंगत विद्यार्थियों के मिलने से इस उद्योग को नई ऊँचाइयाँ हासिल होंगी।
- इस साझेदारी के तहत स्टेनलेस स्टील पर दो मॉड्यूल लॉन्च किये जाएंगे। हरियाणा में सभी सरकारी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिये एक अनिवार्य मॉड्यूल शुरू किया जाएगा। यह मॉड्यूल मटेरियल एवं मेटलर्जी विषय का हिस्सा होगा और इसमें 10 व्याख्यान होंगे। इसे हरियाणा के सभी 25 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संस्थागत रूप दिया जाएगा, जिससे हर साल 3,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
- उक्त पाठ्यक्रम मार्च 2022 से शुरू करने की योजना है। इसके अलावा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पाँचवे सेमेस्टर के छात्रों के लिये 3 क्रेडिट, 42 व्याख्यान का वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार में एक व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित करेगी, जहाँ छात्रों को स्टेनलेस स्टील की बेल्डिंग और पैब्रिकेशन का व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा। इस तरह नौकरी के अवसरों के अलावा छात्रों को उद्योग का अनुभव और प्रशिक्षण भी मिलेगा।

नोट :

एक अनूठे कार्यक्रम 'पदमा'की हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 23 फरवरी, 2022 को हरियाणा सरकार ने महत्त्वाकांक्षी 'प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट (पदमा)' पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- पदमा का मुख्य उद्देश्य सतत् रोज़गार व उद्यमिता के अवसरों पर ज़ोर देने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय रूप से प्रासंगिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा और राज्य के किसानों को उत्पादकों से लेकर प्रोसेसर बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही पूरे हरियाणा में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य के 22 ज़िलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र, हितधारकों के परामर्श, कच्चे माल की उपलब्धता, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और विकास क्षमता के आधार पर सतत् व लागत प्रभावी क्लस्टर बनाने के लिये एक उत्पाद की पहचान की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा चयनित उत्पाद हेतु जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिये प्रत्येक ब्लॉक हेतु एक नया मिनी-औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा, ताकि उत्पाद की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मज़बूत किया जा सके।
- यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) और बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस (बीडीएस) हब के साथ कई नए एमएसएमई को स्थापित करेगा।
- मिनी-औद्योगिक क्लस्टर में उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को उनके सामने आने वाली तकनीकी एवं जागरूकता चुनौतियों से निपटने के लिये प्रशिक्षण सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि एमएसएमई निदेशालय पदमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग है। एमएसएमई निदेशालय के अलावा, अन्य संबंधित विभाग, जैसे- एचएसआईआईडीसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सहयोग करेंगे और कार्यक्रम के सुचारु निष्पादन के लिये आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

राखीगढ़ी

चर्चा में क्यों ?

- 23 फरवरी, 2022 को प्रख्यात पुरातत्त्वविद् वसंद् शिंदे ने बताया कि हरियाणा के हिसार स्थित राखीगढ़ी में हुए शोध को 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक'जर्नल ने 'नाइन ब्रेक थ्रू रिसर्च'की सूची में तथा प्रतिष्ठित जर्नल 'साइंस'ने 'शीर्ष 10' में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किमी. दूर है।
- 6000 ईसा पूर्व (पूर्व-हड़प्पा चरण) से 2500 ईसा पूर्व तक इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिये एएसआई के पुरातत्त्वविद् अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में राखीगढ़ी में खुदाई की गई।
- उल्लेखनीय है कि प्रो. शिंदे ने राखीगढ़ी से संबंधित शोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रो. शिंदे भारतीय इतिहास से संबंधित इन शोधों पर एक पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ इंडिया'का लेखन भी कर रहे हैं।

नोट :

- प्रो. शिंदे ने बताया कि-
  - राखीगढ़ी, लोथल गिलुंड, नुजात आदि स्थलों पर हुई खुदाई में मिले अवशेषों, साक्ष्यों और कंकालों की डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी।
  - आर्यों के आक्रमण और बाहर से आने का सिद्धांत मनगढ़ंत और झूठा है जिसकी पुष्टि पुरातत्त्व और डीएनए की वैज्ञानिक जाँच के आधार पर की जा चुकी है।

प्रदेश के 100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले 31 नागरिक अस्पतालों में मुहैया होगी केटरिंग सेवा

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के 100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले 31 नागरिक अस्पतालों में केटरिंग की सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, ताकि मरीज़ों को अस्पतालों में ही भोजन मुहैया हो सके।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को राज्य के नागरिक अस्पतालों में प्राईवेट कमरों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ व डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के नागरिक अस्पतालों को एयरकंडीशन बनाने का प्रयास जारी है तथा अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।
- गुरुग्राम, हिसार व करनाल में अत्याधुनिक तकनीक से लैस नागरिक अस्पतालों को तैयार किया जाएगा, जिस पर कार्यवाही जारी है।
- प्रदेश के किसी भी नागरिक को उपचार के लिये राज्य से बाहर न जाना पड़े, इसके लिये प्रदेश में उच्च गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएँ नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी की वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किये

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टैगोर थियेटर में हरियाणा साहित्य पर्व के अवसर पर हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी की वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किये।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी व उर्दू भाषा के 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया। ये सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी के अंतर्गत दिये गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चारों अकादमियों के अध्यक्ष हैं।
- आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017 के लिये डॉ. कमल किशोर गोयनका व वर्ष 2018 के लिये डॉ. सुरेश गौतम, 2019 के लिये माधव कौशिक और 2020 के लिये ज्ञानप्रकाश विवेक को 7-7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया गया।
- फख्रे हरियाणा सम्मान वर्ष 2019 के लिये डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम, वर्ष 2020 के लिये डॉ. कुमार पानीपती को 5-5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया गया।
- इसी प्रकार महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2017 के लिये डॉ. पूर्णचंद शर्मा, 2018 के लिये मधुकांत, डॉ. संतराम देशवाल, वर्ष 2019 के लिये डॉ. सुदर्शन रत्नाकर व श्रीमती चंद्रकांता, वर्ष 2020 के लिये डॉ. सुभाष रस्तोगी को 5-5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति-पत्र दिये गए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भाषाओं के साहित्यकार समान होते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी समान होनी चाहिये।

नोट :

- उन्होंने कहा कि हरियाणा की साहित्य अकादमियों की पुरस्कार राशि को लेकर एक समान फॉर्मूला बनाया जाए। अभी तक हरियाणा की चारों साहित्य अकादमियाँ साहित्य के क्षेत्र में अलग-अलग पुरस्कार राशि दे रही हैं।

प्रदेश के हर गाँव व शहर में लगाए जाएंगे 'माइक्रो एटीएम'

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के करीब 9,500 डिपो में 'माइक्रो एटीएम'लगाएगी, ताकि गाँव के लोग भी आवश्यकता अनुसार अपने नज़दीक ही पैसे जमा कर सकें व निकाल सकें। यही नहीं वे बैंक में अपने बैलेंस को भी इसी 'माइक्रो एटीएम'के माध्यम से चेक कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी।
- उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोत्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे राशन डिपो के माध्यम से राशन लेने वाले गरीब व्यक्ति 'पीओएस'(पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से ही अपने राशन की पेमेंट अदा करके एटीएम की तरह अतिरिक्त पैसे भी निकलवा सकें।
- उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकूला में पायलट तौर पर डिपो पर 'माइक्रो एटीएम'लगाई जाएंगी, जिससे राशन कार्ड होल्डरों के अलावा आस-पास के अन्य लोग पैसे निकलवा सकेंगे तथा जमा करवा सकेंगे।
- राज्य सरकार के इस कदम से जहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं डिपो-होल्डरों को भी बैंक की सहायता करने की एवज में कमीशन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य में करीब 9,500 डिपो हैं, जिनके माध्यम से बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है।
- पारदर्शिता लाने के लिये गरीबों के हित में राज्य सरकार ने 'पीओएस'मशीन के माध्यम से पहले राशन वितरण का कार्य शुरू किया था, अब इन्हीं डिपों के माध्यम से 'माइक्रो एटीएम' लगाकर लोगों को पैसे के लेन-देन की स्थानीय स्तर पर सुविधा दी जाएगी। डिपो-होल्डरों को पहले उक्त मशीनें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकंडरी स्कूल व राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थापित एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया। इस लैब के माध्यम से छात्र ब्रह्मांड का रहस्य जान सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- ज़िले में प्रथम चरण में ज़िला मुख्यालय पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल और राजकीय कन्या सीनियर सेकंडरी स्कूल तथा कस्बा बवानीखेड़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार करवाई गई है।
- राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में कल्पना चावला एस्ट्रोनॉमी लैब तथा राजकीय कन्या सीनियर सेकंडरी स्कूल में डॉ. विक्रम साराभाई के नाम से एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार करवाई गई है।
- इस एस्ट्रोनॉमी लैब में बच्चे टेलीस्कोप के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल, चांद व तारों को देख सकेंगे। बच्चे टिमटिमाते तारों के बारे में नई-नई जानकारी हासिल करेंगे। एक लैब में चार टेलीस्कॉप की सुविधा मुहैया करवाने की योजना है।
- एस्ट्रोनॉमी लैब में बच्चों को ब्रह्मांड के बारे में हर सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिये लैब में 25 वर्किंग मॉडल होंगे, जिससे बच्चे जान सकेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों हैं ? तारे क्यों चमकते हैं ? चांद और सूरज कहाँ छिप जाते हैं ? या फिर रात के समय आसमान काला क्यों दिखाई देता है ?

नोट :

- लैब स्थापित करने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं-
  - 21वीं सदी के भारत में सभी छात्रों के अंदर अंतरिक्ष के व्यावहारिक ज्ञान के ज़रिये उत्सुकता जाग्रत् करना।
  - छोटी उम्र से ही सभी बच्चों में साइंटिफिक टेंपर विकसित करना।
  - टेलीस्कोप के माध्यम से सौरमंडल के अन्य ग्रहों को पास से देखना और उनके चित्र कैमरे में कैद करना है।

38वीं राज्यस्तरीय पशुधन प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

- 25 से 27 फरवरी, 2022 तक हरियाणा के भिवानी के हुडा ग्राउंड में आयोजित 38वीं राज्यस्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 38वीं पशुधन प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने 25 फरवरी को किया था।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुधन प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए पशुपालन विभाग की दवाइयों का बजट दुगुना करने की घोषणा की।
- कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस पशुधन प्रदर्शनी का सफल आयोजन कोरोना महामारी के कारण दो साल बाद किया गया है। इसे हर साल आयोजित किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से एंबुलेंस सेवा के लिये 70 मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी तथा कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया बकरियों के लिये भी आरंभ की जाएगी।
- इस प्रदर्शनी में दो हज़ार बेहतर नस्ल के पशु लाए गए, जिनको देखकर अन्य किसानों को भी अपने पशु का खान-पान और नस्ल सुधार करने की प्रेरणा मिली।
- प्रदर्शनी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े सहित 53 श्रेणियों के उत्तम नस्ल के पशुओं को सरकार द्वारा नकद इनाम दिया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार आवंटित किये गए।
- प्रदर्शनी में नस्ल चैंपियन श्रेणी में मुर्रा, हरियाणा साहीवाल और एगज्योटिक नस्ल के प्रत्येक नर व मादा को 2.5 लाख व 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। इस तरह प्रदर्शनी में राज्य सरकार द्वारा उत्तम पशु रखने वाले पशुपालकों को 37 लाख 31 हज़ार 800 रुपए की नकद राशि का वितरण किया गया।
- प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ पशु का इनाम रोहतक निवासी देवेंद्र सिंह के झोटे को मिला। उसके बाद हरियाणा नस्ल में प्रथम स्थान झज्जर ज़िले के गाँव गवालिसन निवासी ब्रह्म प्रकाश की गाय को मिला।
- इसी प्रकार साहीवाल नस्ल में प्रथम स्थान करनाल ज़िले के नवदीप की गाय को मिला। क्रॉस ब्रीड नस्ल में महेंद्रगढ़ ज़िले के गुढा निवासी नीटू की गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार गाय की गीर नस्ल में सोनीपत निवासी वीरेंद्र की गाय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुओं की मुर्रा नस्ल में हिसार निवासी होशियार सिंह की भैंस दूसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार हरियाणा नस्ल में पानीपत निवासी नरेंद्र की गाय दूसरे स्थान पर, साहीवाल नस्ल में करनाल निवासी वासुदेव की गाय तथा क्रॉस ब्रीड नस्ल में महेंद्रगढ़ निवासी नीटू की गाय दूसरे स्थान पर रहीं।
- प्रदर्शनी में भिवानी जिले के गाँव ढाणी माहू निवासी विक्की के बकरे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार भिवानी ज़िले के गाँव नांगल निवासी रजनीश की बकरी प्रथम स्थान पर रही।

नोट :